छत्तीसगढ़

सहकारी समाचार

वर्ष- 22 अंक - 08 जुलाई 2025 द्वितीय अंक (पाक्षिक) RNI NO. CHHHIN/2012/45105 पृष्ठ-12 मूल्य 500/- वार्षिक

छत्तीसगढ़ में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

बिलासपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी आधुनिक एजुकेशन सिटी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर शहर को एक आधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशानिर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशनल सिटी की अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगर पालिक निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि का उपयोग प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विगत दिनों कहा कि बिलासपुर एजुकेशनल सिटी में नालंदा परिसर की स्थापना की जाएगी, जहां 500 छात्र-छात्राएं एक साथ बैठकर फिजिकल एवं डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही तीन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें कुल 48 हॉल सेटअप (1 सेटअप में 1 हॉल, 2 कक्ष और 1 टॉयलेट) तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था में एक साथ 4,800 विद्यार्थियों के कोचिंग क्लास अटेंड करने की सुविधा रहेगी।

छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए 700 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी

किया जाएगा। वहीं, बाहर से आने वाले लगभग 1000 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी निर्मित की जाएगी।

खेलकूद और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल सिटी में एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान तथा सुंदर गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही, वाहनों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी ताकि आने-जाने में कोई असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपये होगी और इसके निर्माण कार्य की कार्य योजना नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिससे बिलासपुर एजुकेशनल सिटी प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के पश्चात बिलासपुर शहर ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिलासपुर में एसईसीएल का मुख्यालय और रेलवे का डीआरएम कार्यालय भी स्थित है, जिससे यह शहर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय, आठ महाविद्यालय, लोक सेवा आयोग, व्यापम और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले करीब 100 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रदेश के 50,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान देती है। हमारी यह अटल प्रतिबद्धता है कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक संसाधनों, उन्नत अधोसंरचना और प्रेरक वातावरण में अपनी क्षमताओं को संवार सके और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके। बिलासपुर एजुकेशन सिटी का निर्माण इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह न सिर्फ बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का एजुकेशनल हब बनाएगा, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं को उच्चस्तरीय सुविधाओं में अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देगा। नालंदा परिसर, बहुमंजिला कोचिंग भवन, डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, खेल मैदान और ग्रीन जोन – ये सभी सुविधाएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को समर्पित होंगी।

> मुझे विश्वास है कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और हमारे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।
>
> **- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय**

बलौदाबाजार जिले के छह धान खरीदी केंद्रों में बनेंगे शेडयुक्त चबूतरा

■ **मंत्री टंकाराम वर्मा ने किया उपार्जन केंद्रों में शेडयुक्त चबूतरा निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, लगभग 2 करोड़ रुपये के नवीन विकास कार्यों को मिली स्वीकृति**

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकाराम वर्मा ने मंगलवार को बलौदाबाजार जिले के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले छह धान उपार्जन केंद्रों में शेडयुक्त कंक्रीट चबूतरा निर्माण कार्य का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। यह निर्माण कार्य ग्राम देवरी, सलोनी, करमदा, रसेड़ा, भरसेला एवं लटुआ के उपार्जन केंद्रों में किया जाएगा, जिसकी प्रति केंद्र लागत 21.80 लाख रुपये के है।

श्री वर्मा ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये के नवीन कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके अंतर्गत ग्राम सोनपुरी, बोईरडीह, बेमेतरा, धंवई, भाठागांव, सलोनी, देवरी एवं शुक्लाभांठा में प्रत्येक स्थान पर चेक डेम निर्माण हेतु 20-20 लाख रुपये तथा ग्राम बुड़गहन में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

ये भी रहे मौजूद

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना यादव, जिला अध्यक्ष श्री आनंद यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

प्रदेश में चहुंमुखी विकास कार्य जारी : वर्मा

इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में चहुँमुखी विकास कार्य निरंतर जारी है। राज्य सरकार आमजन के कल्याण एवं सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी स्वीकृत कार्यों को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा और विकास की गति में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक लोकनृत्य और संगीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया गया।

शाखा प्रबंधक, सुपरवाइजर और समिति प्रबंधकों को दिया गया नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का सहकारी प्रशिक्षण

रायपुर। जिला रायपुर की समस्त शाखाओं के शाखा प्रबंधक, सुपरवाइजर और समिति प्रबंधकों के लिए 19 जुलाई को इफ्को ने कार्यक्रम का आयोजन किया। नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का धान की फसल में किसानों से सही उपयोग करवाने हेतु सहकारी प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होटल एम्बेसडर, रायपुर छत्तीसगढ़ में श्रीमती अपेक्षा व्यास, सीईओ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेश कुमार राठौर, राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को छत्तीसगढ़ द्वारा की गई। कार्यक्रम में 135 प्रबंधक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में नैनो डीएपी तरल से धान बीज उपचार, लाईचौपा धान बीज उपचार, धान थरहा उपचार एवं धान रौपा जड़ उपचार की विधियों को विस्तार से डिमांस्ट्रेशन करके समझाया गया। नैनो यूरिया के उपयोग का कब और कैसे उपयोग करना है, बताया गया। सभी फसलो में दानेदार खाद की आधी मात्रा का उपयोग प्रारंभिक अवस्था में 30-35 दिनों में करना है एवं इसके बाद टाप ड्रेसिंग के समय पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को मिलाकर, पत्तों पर छिड़काव करें (प्रति 15 लीटर पम्प में 60 एम.एल. नैनो डीएपी और 60 एम.एल. नैनो यूरिया मात्रा) धान की गबौट अवस्था (पोटर पानी) के 07 दिन पूर्व नैनो यूरिया का छिड़काव करें (60 एम.एल. प्रति 15 लीटर पम्प) इस समय दानेदार यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए।

नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करें : व्यास

श्रीमती अपेक्षा व्यास सीईओ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को वर्तमान परिस्थितियों में प्रोत्साहित करने को कहा। फसल बीमा, धान खरीदी पंजीयन, ट्रैक्टर फायनेंस के कार्यो में गति लाने का निर्देश दिया गया। श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधक विपणन इफ्को रायपुर द्वारा प्रबंधकों को समितियों को लाभ मे लाने के लिए नैनो डीएपी और नैनो डीएपी के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया उपयोग प्रोत्साहित करने से समितियों को परिवहन ख़र्च में उल्लेखनीय कमी हो सकती है। नैनो डीएपी नैनो यूरिया बाटल ,किसानों को भी लाने ले जाने में आसान है और भंडारण करने में आसान है। कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश कुमार गांधी इफ्को उपक्षेत्र- प्रबंधक कृषि सेवा और आभार प्रदर्शन श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधक विपणन इफ्को रायपुर द्वारा किया गया।

दानेदार उर्वरकों का इस्तेमाल आधा करें : राठौर

श्री राठौर, राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को द्वारा किसानों के द्वारा अत्यधिक रासायनिक खादों के उपयोग करने से खेत की मिट्टी -पानी और हवा को हों रहे नुकसान के बारे में समझाया गया। वर्तमान खरीफ धान फसल में नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और दानेदार खादों का उपयोग आधा करने से हम खेत की मिट्टी पानी को हो रहे नुकसान को कम कर सकते हैं और धान फसल की भरपूर पैदावार ले सकते हैं। नैनो उर्वरकों के उपयोग से हम खाद पर भारत सरकार द्वारा की जा रही सब्सीडी के लाखों करोड़ रुपए भी बचा सकते हैं। श्री दिनेश कुमार गांधी उपक्षेत्र- प्रबंधक कृषि सेवा द्वारा जैविक खाद एनपीके कन्सौर्टिया तरल का उपयोग करने का तरीका विस्तार से बताया गया।

नक्सलियों का गढ़ रहे झिरम गांव में रखा गया सहकारी प्रशिक्षण

सुकमा। सहकार से समृद्धि आती है, सहकारिता से रोजगार के अवसर का सृजन होता है। जिससे संपन्नता आती है और गांव का आर्थिक विकास होता है। ग्रामीण कृषक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए संघ के मुख्य प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे ने 16 जुलाई को झिरम गांव के स्कूल भवन में सहकारी प्रशिक्षण संपन्न किया गया।

सुकमा जिले के अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले झिरम गांव, जहां कुछ वर्षो पहले छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं का नक्सलियों द्वारा नरसंहार किया गया था। आज वह झिरम गांव शांति के साथ शासकीय योजनाओं से अपने आप को जोड़कर विकास की मुख्य धारा में आने को लालायित है। विगत दिवस सहकार से समृद्धि लाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के तत्वाधान में संभागीय कार्यालय जगदलपुर के प्रशिक्षण इकाई द्वारा सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

सहकारी समिति गठन की भी दी गई जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन पर भी चर्चा करते हुए दुग्ध पालन, मछली पालन सहकारी समितियां के गठन पंजीयन आदि पर विस्तार से ज्ञान करवाया गया। प्रशिक्षण वर्ग में सरपंच सोमू राम व झिरम प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक श्री मंडावी व कवाचि के साथ-साथ संघ के श्री रोमांचल पाणिग्राही का सहयोग रहा।

अंधेरे से उजाले की ओर
पूवर्ती गांव के अर्जुन की उड़ान

रायपुर। नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर अंचल का एक नाम जो आज उम्मीद और बदलाव की मिसाल बनकर उभरा है वह है माडवी अर्जुन। सुकमा जिले के अति-दुर्गम और माओवादी हिंसा से वर्षो त्रस्त रहे पूवर्ती गांव के इस बालक ने जवाहर नवोदय विद्यालय, पेंटा (दोरनापाल) में छठवीं कक्षा में चयन पाकर इतिहास रच दिया है। यह केवल एक छात्र की जीत नहीं, बल्कि उस उम्मीद का संकेत है जो अब बस्तर के कोने-कोने में अंकुरित हो रही है।

माडवी अर्जुन जिस पूवर्ती गांव का रहने वाला है , दरअसल वह नक्सलियों के कमांडर हिड़मा का पैतृक गांव है। एक दौर था, जब पूवर्ती नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ माओवादी जन अदालत लगाकर आतंक और ग्रामीणों भाग्य का फैसला सुनाते थे। अब वही पूवर्ती गांव, शिक्षा और विकास के नए सूरज की किरणें देख रहा है। अर्जुन की इस उपलब्धि ने यह दिखा दिया है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अगर अवसर और मार्गदर्शन मिले तो सफलता जरूर मिलती है।

अर्जुन वर्तमान में बालक आश्रम सिलगेर में पढ़ाई कर रहा था। उसके घर में न बिजली है, न पक्की छत। उसके माता-पिता खेती और मजदूरी कर किसी तरह घर चलाते हैं। फिर भी, अर्जुन ने कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मेहनत और आश्रम शिक्षकों के समर्पण से यह उपलब्धि अर्जित की।

बीते डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा

चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान ने बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में परिवर्तन की नींव रखी है। पूवर्ती जैसे क्षेत्र जहां पहले सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं, अब वहां सड़क निर्माण, सुरक्षा बलों के कैंप, गुरुकुल विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और उचित मूल्य दुकानें शुरू हो चुकी हैं।

पूवर्ती में अब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षा बलों की देखरेख में चल रहे गुरुकुल ने एक प्रेरणादायी माहौल देना शुरू किया है। अर्जुन की सफलता इसी सतत प्रयास की पहली बड़ी उपलब्धि है।

जिला कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने कहा कि पूवर्ती जैसे दुर्गम और माओवाद प्रभावित गांव से नवोदय विद्यालय में चयन, न केवल अर्जुन की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह जिले की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है। हम हर बच्चे को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहते हैं।

बस्तर की महिलाओं को दिया गया सहकारी प्रशिक्षण

बस्तर। ग्राम बड़े तामाकोनी पारा के आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान सहकारिता का महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, सदस्यता, सदस्य के अधिकार, कर्तव्य, बैठक, बैंक लिंकिंग, व्यवसाय विकास आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के महिलाओं का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 11 जुलाई को किया गया। प्रशिक्षण में उक्त सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण को सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

उद्यानिकी फसल से संतेर पोटाई हुए आर्थिक रूप से सशक्त

रायपुर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उद्यानिकी विभाग की पहल से जिले के ग्राम भाटपाल निवासी संतेर पोटाई की किस्मत बदल गई है। पहले केवल धान की खेती करने वाले संतेर अब आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों से विविध सब्जियों की खेती कर न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं।

संतेर पोटाई, पिता रैजूराम, परंपरागत खेती के जरिए अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। लेकिन उत्पादन में गिरावट और लागत में बढ़ोतरी के कारण आय लगातार घट रही थी। ऐसे समय में उन्हें उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विस्तार से मार्गदर्शन लेकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन, टमाटर, लौकी, तोरई एवं भिंडी की खेती शुरू की। संतेर ने उन्नत तकनीकों और मल्चिंग विधि का प्रयोग करते हुए लौकी, टमाटर, करेला और मिर्च की खेती की। इससे उनकी कुल लागत लगभग 80 हजार रही, जबकि फसल की बिक्री से उन्हें 4 लाख की आमदनी हुई। शुद्ध लाभ 3 लाख 20 हजार रहा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। संतेर की इस सफलता को देखते हुए आसपास के कई किसान भी अब उद्यानिकी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। संतेर पोटाई अपनी फसलें स्थानीय बाजारों और आश्रम छात्रावासों में विक्रय करते हैं। संतेर पोटाई की यह सफलता न सिर्फ सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि मार्गदर्शन और मेहनत से किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

डीएपी बना किसानों की नई ताकत, उत्पादन बढ़ाने के साथ लागत में भी कटौती

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते किसानों को अब परंपरागत डीएपी का आधुनिक और किफायती विकल्प नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। खरीफ सीजन 2025 के लिए सभी जिलों की सहकारी समितियों में इसकी सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि को लेकर सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में नैनो डीएपी को प्राथमिकता दी गई है, जो मात्र 500 मि.ली. की बोतल में 45 किलो परंपरागत डीएपी के बराबर पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है, बल्कि फसल को संतुलित पोषण मिलने से उत्पादन भी बढ़ता है।

कोरबा जिले में नैनो डीएपी वितरण का प्रभावी क्रियान्वयन- कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में जिले में अब तक 8514 नैनो डीएपी और 14233 नैनो यूरिया की बोतलें प्राप्त की गई, जिनमें से 18087 बोतलें किसानों को वितरित की जा चुकी हैं। शेष 4660 बोतलें सहकारी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। राज्यभर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, सहकारी समितियों, और जनसंपर्क तंत्र के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पोस्टर, बैनर, ग्राम बैठकों और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को नैनो डीएपी के लाभ और उपयोग की विधि बताई जा रही है।

सौर ऊर्जा से पानी, बिजली एवं खेती में आ रहा सकारात्मक बदलाव

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर संयंत्रों से हो रहा सर्वांगीण विकास

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन के परिणाम स्वरूप सरगुजा जिले के सुदूर अंचल सहित समूचे राज्य में सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा जल जीवन मिशन के तहत् पीने का पानी पहुंचाने, खेतों की फसलों में सिंचाई सुविधा और रात में बिजली पहुंचाने सुदूर ईलाकों तक की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

सरगुजा जिले के डांडगांव में 13 सोलर ड्यूल पंप स्थापित कर ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा दी गई है। जिससे ग्रामीणों के घर पर ही स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। वहीं गांव में 4 सोलर हाई मास्ट लाइट स्थापित कर रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। क्रेडा द्वारा राज्य के मैदानी और अंदरूनी इलाकों में सोलर ड्यूल पंप, सोलर हाईमास्ट एवं सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना कर ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। संयंत्रों की अकार्यशीलता की सूचना मिलने पर 'सौर समाधान एप' के माध्यम से तत्काल कार्यवाही कर संयंत्रों को पुनः क्रियाशील बनाया जा रहा है।

क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश सिंह राणा द्वारा परियोजनाओं की सतत निगरानी कर गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। सीईओ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्रेडा केवल संयंत्र स्थापित करने वाली संस्था न होकर सेवा की निरंतरता और जनविश्वास की संरक्षक संस्था है।

अब तक सरगुजा संभाग में लगभग 8 हजार 848 सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 हजार 094 से अधिक सोलर पेयजल पंप स्थापित किए गए हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ ग्रामीणों को राहत मिल रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी सुलभ हुई है।

मनरेगा से प्राकृतिक संतुलन की ओर एक सशक्त पहल

■ दारापाल की कच्चा घाटी में कंटूर ट्रेंच निर्माण से किसानों को मिल रहा लाभ

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में न केवल रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड भैरमगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर दूर, जिला दंतेवाड़ा की सीमा से लगे ग्राम पंचायत दारापाल के कच्चा घाटी में 300 नग कंटूर ट्रेंच का निर्माण कर एक अनुकरणीय कार्य किया गया है।

तीव्र ढलान वाली इस घाटी में वर्षों से वर्षा जल का तेज बहाव खेती योग्य भूमि को क्षति पहुँचा रहा था। इस समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया गया। इससे घाटी के आसपास की भूमि में नमी की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़-पौधों को जीवित रहने में मदद मिल रही है।

घाटी के ठीक नीचे 25 कृषकों की लगभग 150 एकड़ कृषि भूमि स्थित है, जिन्हें इस कार्य से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। कंटूर ट्रेंच के अतिरिक्त घाटी के निचले हिस्से में एक तालाब का निर्माण भी किया गया है, जिससे बहते हुए पानी को रोका जा सके और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके।

ग्राम पंचायत दारापाल की तकनीकी सहायक ने जानकारी दी कि कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मार्गदर्शन में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। कन्टूर ट्रेंच निर्माण से जहां भूमि कटाव की समस्या पर नियंत्रण पाया गया है, वहीं इससे मृदा संरक्षण और जल संचयन को भी बढ़ावा मिला है। इस कार्य पर ?4 लाख 68 हजार की लागत आई है तथा कुल 1929 मानव दिवस का सृजन किया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी प्राप्त हुआ।

ग्राम दारापाल निवासी कृषक श्री राजकुमार कश्यप, जिनकी 7 एकड़ भूमि घाटी के निचले हिस्से में स्थित है, ने बताया कि पूर्व में बारिश के दौरान घाटी से तेज बहाव के साथ झाड़ियाँ और कचरा खेतों में आकर फसल को नष्ट कर देते थे और मेड़ों का कटाव भी होता था। अब कंटूर ट्रेंच बनने से यह समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य में श्रमिक के रूप में भाग लेने से उन्हें मजदूरी का लाभ भी मिला है।

किसान चोहलदास साहू को धान पैडी ट्रान्सप्लांटर से रोपा लगाने में हो रही मेहनत एवं समय की बचत

■ **कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन के तहत धान पैडी ट्रान्सप्लांटर के लिए मिला 4 लाख 10 हजार रूपए का अनुदान**

राजनांदगांव। कृषि के खेती किसानी की नवीनतम तकनीक एवं आधुनिक यंत्रों ने कृषि कार्यों को आसान बना दिया है। धान पैडी ट्रान्सप्लांटर मशीन से मेहनतकश किसानों के श्रम एवं समय की बचत हो रही है। इस मशीन के माध्यम से निर्धारित दूरी पर रोपा लगाने का कार्य बहुत सरल हो गया है। रोपा लगाने का कार्य श्रममाध्य है और समय भी बहुत लगता है। ऐसे में धान पैडी ट्रान्सप्लांटर मशीन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम केसला के प्रगतिशील किसान श्री चोहलदास साहू के लिए धान पैडी ट्रान्सप्लांटर मशीन बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि शासन की योजना अंतर्गत कृषि विभाग के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से धान पैडी ट्रान्सप्लांटर के लिए कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन के तहत 4 लाख 10 हजार रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि मशीन की कुल लागत 9 लाख रूपए है। उन्होंने कहा कि इस मशीन से रोपा लगाने का कार्य आसान हो गया है।

प्रगतिशील किसान श्री चोहलदास साहू ने बताया कि उनके पास 10 एकड़ जमीन है। धान पैडी ट्रान्सप्लांटर से रोपा लगाने में मेहनत एवं समय की बचत हुई तथा फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। रोपा लगाने में कृषि लागत में भी कमी आई है। एक ही दिन में 4 एकड़ तक भूमि में रोपा लग जाता है, जिससे खुशी होती है। थरहा को लाने ले जाने में भी सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि मशीन से थरहा लगाने पर घना लगता है और पौधों का विकास भी अच्छा होता है। मशीन से निर्धारित दूरी पर रोपा लगने से बीमारी भी कम होती है और पौधों का अच्छा विकास हो जाता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। शासन की किसानहितैषी योजनाओं से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। जिससे वे नये कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मशीन से रोपा लगाने पर प्रति एकड़ 31 क्विंटल धान का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा वे पैडी ट्रान्सप्लांटर से अन्य किसानों के लिए भी प्रति वर्ष लगभग 40 एकड़ भूमि में किराए से रोपा लगा रहे है।

जिले के किसान शासन की योजनाओं के तहत कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्र ट्रेक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, हैप्पी सीडर, स्प्रेयर, राईस ट्रायर, स्ट्रा बेलर, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, मल्चर, स्ट्रॉ रीपर, पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, कल्टीवेटर, एमबी प्लाऊ, लेवलर, केजव्हील, रीजरे, बंड फारमर, हैरो, चिसल प्लाऊ, जीरो टिल सीड ड्रिल, शक्ति चलित विनोविंग फेन, पॉवर टिलर, कम्बाईन हार्वेस्टर, ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव जैसे कृषि यंत्र के माध्यम से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और कृषि यंत्र एवं उपकरण खरीद रहे हैं।

कृषि यंत्रों से आसान हुई खेती

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी योजनाओं एवं यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने से खेती-किसानी अब सुविधाजनक हो गई है। शासन की कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए वृहद पैमाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक ग्राम केसला के किसान श्री चोहलदास साहू को धान पैडी ट्रान्सप्लांटर मशीन के लिए 4 लाख 10 हजार रूपए का अनुदान मिला है। कृषक श्री साहू ने बताया कि मशीन की कुल कीमत 9 लाख रूपए है।

पैडी ट्रान्सप्लांटर से रोपा लगाने का काम काफी तेज, आसान और सटीक हो गया है। इससे श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है। इसकी मदद से एक दिन में 4 एकड़ भूमि में रोपा लगाया जा सकता है, जिससे खेती का काम पहले की तुलना में काफी तेज हो गया है। इसके उपयोग से फसल की बुवाई में पौधों की दूरी संतुलित रहती है, जिससे बीमारियां कम होती हैं और फसल का विकास बेहतर होता है। श्रमिकों पर निर्भरता भी घटी है और कृषि लागत में कमी आई है। मशीन से रोपा लगाने पर प्रति एकड़ 31 क्विंटल तक धान उत्पादन होता है। कृषक श्री साहू ने बताया कि पैडी ट्रान्सप्लांटर से धान की रोपाई के साथ-साथ अन्य किसानों की जमीन पर भी किराए से रोपा लगाने का कार्य कर रहे हैं। प्रति एकड़ 3,500 रूपए की दर से लगभग 40 एकड़ भूमि पर रोपा लगाने से उन्हें करीब 1 लाख 20 हजार रूपए की अतिरिक्त आय भी हुई है। शासन की कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन योजना के तहत किसानों को अनुदान सहायता पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ड्रोन, स्प्रेयर, सीड ड्रिल, मल्चर जैसे आधुनिक कृषि प्रदान किए जा रहे है, जिससे कृषि के क्षेत्र में आसानी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। राजनांदगांव जिले में वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा किसानों को कृषि यंत्र खरीदने हेतु कुल 3.31 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। शासन की इन योजनाओं से किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर तकनीक आधारित आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और खेती का काम सरल होता जा रहा है।

पावर टिलर बन रहा है बदलाव का आधार

रायपुर। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब जैविक खेती के साथ-साथ आधुनिक खेती के उपकरण को अपनाने के लिए भी तेजी से आगे आ रहा है। जिला प्रशासन ने हाल ही में यहां के 75 प्रगतिशील किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों को पावर टिलरों का वितरण किया है।

सबसे बड़ी बात है कि इन आधुनिक खेती के उपकरणों का उपयोग व्यक्तिगत खेती में ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से इनके सामूहिक उपयोग मॉडल पर भी जोर दिया गया है, जिससे गांव के अन्य किसान भी इसका लाभ उठा सकें।

पावर टिलर के माध्यम से किसान खेतों की गहरी जुताई करने के साथ-साथ मिट्टी को बारीक करने और जैविक खादों को समरस रूप से मिलाने में कर रहे हैं। जहां पहले पारंपरिक हल से खेत की जुताई में दो से तीन दिन लगते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। पावर टिलर का आकार छोटा और संचालन सरल होने के कारण यह छोटे जोत के किसानों के लिए भी उपयुक्त है।

ग्राम हीरानार के किसान लूदरुराम और ग्राम कासौली के सुरेश नाग बताते हैं कि पावर टिलर के उपयोग से खेती करना अब

पहले से ज्यादा आसान हो गया है। समय की बचत हो रही है। उत्पादन में भी सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मल्टीपरपज मशीन न केवल जुताई के काम आती है, बल्कि मिट्टी पलटने, कतार बनाने, निंदाई-गुड़ाई, खाद मिलाने और ट्रॉली से परिवहन जैसे कार्यों में भी सहायक है। इससे श्रम लागत में कमी आई है और जैविक खेती भी टिकाऊ और लाभदायक बना है। विशेषकर युवा किसान भी अब आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बस्तर अंचल का दंतेवाड़ा जिला अब अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा, उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के साथ-साथ जैविक खेती की दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है।

खाद बीज की उपलब्धता से आसान हुई खेती

रायपुर। खरीफ के लिए किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सहजता से खाद बीज की उपलब्धता के चलते खरीफ फसलों की बुवाई का काम तेजी से जारी है। मुंगेली जिले में खरीफ 2025 के लिए किसानों को उनकी डिमांड के आधार पर अब तक 37535 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक और 14 हजार 855 क्विंटल बीज वितरण किया जा चुका है। जिले की सभी सोसायटियों में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक और खरीफ फसलों के प्रमाणिक बीज वितरण हेतु उपलब्ध है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुंगेली जिले में चालू खरीफ सीजन में 60620 मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 45145 मैट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया गया है। जिसमें से 37 हजार 535 टन उर्वरक का उठाव किसानों ने किया है। इसी तरह 14 हजार 855 क्विंटल बीज वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 17 हजार 377 क्विंटल बीज का भंडारण कर किसानों को पूरी मात्रा में बीज का वितरण किया जा

चुका है।

डीएपी खाद की संभावित कमी को देखते हुए एनपीके, एसएसपी और यूरिया जैसे उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। इनमें एनपीके को सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया है। आधुनिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भी उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब तक 6,497 बोतल नैनो यूरिया में से 3,207 बोतलों का वितरण, और 3,114 बोतल नैनो डीएपी में से 1,085 बोतलों का वितरण किसानों को किया गया है। यह उर्वरक मिट्टी की गुणवत्ता को सुरक्षित रखते हुए पौधों को आवश्यक पोषण देते हैं।

कृषि विभाग द्वारा जिले की 66 सेवा सहकारी समितियों और निजी विक्रय केन्द्रों में इन उर्वरकों का भंडारण किया गया है। जिले में बीज और खाद विक्रय केन्द्रों की नियमित जांच की जा रही है। अब तक 9 बीज विक्रेताओं और 5 खाद विक्रेताओं पर अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। बीज और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता तथा प्रशासन की कड़ी निगरानी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। सभी सेवा सहकारी समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को खाद प्राप्त करने में कठिनाई न हो और वितरण पूर्ण पारदर्शिता से किया जाए।

बस्तर में 'बिहान' से लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर महिलाएं

■ **एकीकृत खेती और संबद्ध गतिविधियों से बढ़ रही आय**

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के तहत राज्य में महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। बस्तर जिले में जगदलपुर, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा और दरभा - इन चार विकासखंडों में चिन्हांकित 16 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स के माध्यम से लगभग 4600 परिवारों को एकीकृत खेती और संबद्ध गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य समूह से जुड़ी महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है, जिससे वे सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर सकें।

'बिहान' परियोजना के तहत, पारंपरिक खेती से हटकर उन्नत किस्म के बीजों और नई तकनीकों का उपयोग करके अधिक मात्रा में उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही, पौधों में होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

सब्जी उत्पादन से आत्मनिर्भरता की राह

परियोजना के पहले चरण में, स्वसहायता समूह से जुड़ी 1800 से अधिक दीदियों ने अपने घरों के बाड़ी में 5 से 10 डिसमिल भूमि पर लतर वाली सब्जियों जैसे करेला, बरबटी, लौकी, तरोई और गिलकी का उत्पादन शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने मल्चिंग और मचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है।

ग्राम कलचा के जयंती बघेल बिहान स्व सहायता समूह' की सदस्य हैं और लगभग 15 डिसमिल में सब्जी उत्पादन कर रही हैं। इसी तरह ग्राम नेगीगुड़ा की पद्मा बघेल 'रुपशिला स्व सहायता समूह' से जुड़ी हैं और 10 डिसमिल में सब्जी उगा रही हैं। ग्राम बीजापुट की चंपा बघेल 'जीवन ज्योति स्व सहायता समूह' की सदस्य हैं और 25 डिसमिल में, जबकि ग्राम करणपुर की हीरामणि 'दुलार देई स्व सहायता समूह' की सदस्य हैं और 5 डिसमिल में सब्जी उत्पादन कर रही हैं।

इस पहल से गांवों में सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, जिससे न केवल स्वयं के परिवार के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि बाजार से सब्जी खरीदने पर होने वाले खर्च में भी कमी आ रही है। इस बचत राशि का उपयोग महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, संपत्ति निर्माण या नए व्यवसाय में कर सकती हैं।

इसके अलावा, अतिरिक्त सब्जी को स्थानीय बाजारों और छोटी मंडियों में बेचकर महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।द् भविष्य में, बस्तर में उत्पादित सब्जियों की मांग के अनुरूप जिले के बाहर भी इनकी आपूर्ति की योजना है।

एक सदस्य, कई आजीविका गतिविधियां

'बिहान' परियोजना का लक्ष्य एक सदस्य को तीन से चार आजीविका गतिविधियों से जोड़ना है। इसमें सब्जी उत्पादन के अलावा मक्का, पशुपालन (मुर्गी, बकरी), वनोपज (इमली प्रसंस्करण), मछली पालन और लघु धान्य उत्पादन जैसी संबद्ध गतिविधियां भी शामिल हैं, जो महिलाओं की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

'बिहान' की यह पहल बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे सही मायने में 'लखपति दीदी' बन सकेंगी।

अनुभव एवं ज्ञान से हर समस्या का हल संभव- रंजना साहू

धमतरी। जिला सहकारी संघ धमतरी के तत्वाधान में जिले के 74 लैंप्स व पैक्स के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 30 जुलाई 2025 को नीलामी परिसर वन विभाग धमतरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य, नेतृत्व विकास, सहकार से समृद्धि एवं कृषि संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धमतरी रंजना डिपेंद्र साहू, अध्यक्षता सभापति सहकारिता जिला पंचायत धमतरी मीना साहू , विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच डेमू साहू, अति विशिष्ट अतिथि उपायुक्त सहकारिता प्रदीप ठाकुर, छग राज्य सहकारी संघ रायपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी सी ध्रुव, डॉ ए एन दीक्षित प्रवक्ता एवं पूर्व प्राचार्य पीजी कॉलेज, डॉ ईश्वर सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक केवीके धमतरी, सुश्री सुमन ध्रुव सहायक आयुक्त सहकारिता, बलराम पुरी गोस्वामी नोडल अधिकारी एवं अन्य अतिथि सी पी साहू प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी संघ धमतरी, डॉ दीपिका चंद्रवंशी उद्यानिकी विभाग, पूर्णिमा घानेकर एससीआई, लाल बहादुर सिंह फील्ड ऑफिसर इफ्को, किशन यदु शाखा प्रबंधक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रंजना साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि समस्त मनोनीत प्राधिकृत अधिकारियों का चयन कर योग्य व्यक्तियों को ही जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान परिपेक्ष में सहकारिता को समझना एक टेढ़ी खीर है। सहकारिता में एक दूसरे को समझना और कार्य करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है।

छग राज्य सहकारी संघ के सीईओ पीसी ध्रुव ने बताया कि सहकारिता ने कृषकों को ऋण जाल से मुक्त कराया है, जिसके फलस्वरूप शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण वितरण हो रहा है। जिला संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू ने जिला संघ के क्रियाकलापों से अवगत कराया।

कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ डॉ ए एन दीक्षित ने अपने वक्तव्य में कहा कि सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही उनकी योग्यता के आधार पर मनोनीत कर विशिष्ट एवं पूर्ण कुशलता पूर्वक कार्य करने हेतु यह उपयुक्त अवसर प्राप्त होता है जिसमें से आप सभी हैं। सहकारिता में शिक्षण और प्रशिक्षण का बहुत अधिक महत्व है। अद्यतन बने रहने के लिए निरंतर प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक है। वर्तमान में सभी पैक्स में मॉडल बायलॉज अपना लिया गया है। उनके निरंतर अध्ययन करने से जो भी कार्य संस्था हित में करने हो वह सरल हो जाएगी। उन्होंने रोचडेल पायनियर का उदाहरण देकर सहकारिता के सिद्धांत एवं आदर्श समिति के सफल संचालन पर विस्तार से चर्चा किया। अगले वक्ता राजेश साहू व्याख्याता सहकारी प्रशिक्षण केंद्र रायपुर ने एक अच्छे लीडर के गुण बताएं एवं लीडरशिप की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने मल्टी पर्पस पैक्स की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पंजाब के नूरपुर बेट मल्टी पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्देश्य पर आधारित कार्य जैसे डीजल पंप का संचालन, जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, ग्रॉसरी शॉप, हार्डवेयर शॉप, मॉडर्न एग्रो मशीनरी सर्विसेज, ड्रोन सर्विस, निः शुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आदि के बारे में बताया, जिससे समस्त प्राधिकृत अधिकारी रोमांचित भी हुए। पुरुषोत्तम सोनी व्याख्याता सहकारी प्रशिक्षण केंद्र रायपुर ने सहकारी समितियों की प्रबंध व्यवस्था, पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी दी।

प्रशिक्षण से होगा नेतृत्व क्षमता का विकास : मीना साहू

इसी कड़ी में मीना साहू ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में कृषकों को जो खाद बीज की समस्याएं आती है उनका त्वरित निदान किया जाना चाहिए। प्रदीप ठाकुर उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि जिला संघ धमतरी अपने उद्देश्य के अनुरूप समस्त सहकारी संस्थाओं हेतु समय-समय पर वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जो पदाधिकारी के नेतृत्व क्षमता में विकास हेतु लाभप्रद होता है। सहकारिता की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने से ही सहकारिताएं सफल हो सकती है। बलरामपुरी गोस्वामी ने बताया कि मिलजुलकर कार्य करने का नाम ही सहकार है। हमें सहकारिता को सफल बनाने के लिए संकल्पित होना होगा। सहकारिता भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। भारतीय कृषकों की उन्नति के लिए सहकारिता विभाग निरंतर प्रयासरत है।

उत्कृष्ट बीज उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता : ईश्वर सिंह

डॉक्टर ईश्वर सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कृषि विज्ञान केंद्र में धान के विभिन्न वैरायटियों के रिसर्च कार्य के संबंध में अवगत कराया। उत्कृष्ट धान बीज तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में केवीके कार्य करके जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहे है। लाल बहादुर सिंह फील्ड ऑफिसर इफ्को ने यूरिया के प्रयोग को कम करके नैनो यूरीया नैनो डीएपी के उपयोग के संबंध में जानकारी दी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारी संस्थाओं में हुए विविध आयोजन

इफको ने रखा सहकारी प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पौधे भी रोपे गए

महासमुंद। होटल अकेशिया महासमुंद में 24 जुलाई को इफको के द्वारा सहकारी प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर से सी.ई.ओ. श्रीमती अपेक्षा व्यास, एडिशनल सी.ओ. श्री एस.पी चंद्राकर, डी.आर श्री द्वारीकानाथ नोडल श्री अविनाश शर्मा इफको के राज्य कार्यालय से उप-क्षेत्र प्रबंधक श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार गोले, इफको एमसी से श्री मनीष, महासमुंद क्षेत्रीय अधिकारी श्री साजिद रज़ा, साथ ही महासमुंद जिला के सभी शाखा के शाखा प्रबंधक, पर्यवेक्षक एवं साथ में 130 समिति के समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

उर्वरकों के उपयोग की विधि समझाई गई

मौजूद लोगों को इफको के उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। मुख्य रूप से नैनो डीएपी का अभी वर्तमान में उपयोग किस प्रकार करवाना है, उसके बारे में लाइव डेमो करके दिखाया गया नैनो डीएपी का बीज उपचार, लाई चोपा उपचार साथ ही रोपा उपचार कैसे करवाना है करके दिखाया गया। जिसमें बताया गया कि, 5 कि.ग्रा. बीज उपचार के लिए 25 एम.एल. (एक ढक्कन) नैनो डीएपी को पहले थोड़े पानी में मिलाए उसके बाद उस घोल को बीज में अच्छी तरह मिला कर 20 मिनट के लिए छांव में सूखने के लिए रख देवे और उसके बाद उसकी बोवाई करे, इसके अलावा थरहा उपचार के लिए 5 ली. पानी में 25 एम.एल. नैनो डीएपी की दर से घोल तैयार करे और उस घोल में थरहा के जड़ को 20 मिनट के लिए डूबा कर रखे उसके पश्चात रोपाई करे। बीज एवं थरहा उपचार करने से पौधो में जड़ों का प्रारंभिक

विकास सामान्य पौधे की तुलना में जादा अच्छा होता है। इसके बाद 25 -35 दिन बाद (जब पत्तियां अच्छी विकसित हो जाए) 1ली. पानी में 4 एम एल नैनो डीएपी एवं 4 एम एल नैनो यूरिया की दर से पत्तियों में छिडक़ाव करें। अंत में गभोंट अवस्था में 4 एम एल प्रति लीटर पानी की दर से नैनो यूरिया का छिड़काव करे।

किसान भूषण साहू ने बताए अनुभव

नैनो उर्वरकों का छिड़काव करने से रोग एवं कीट की समस्या कम होती है। कार्यक्रम में इफको के विभिन्न उत्पाद नैनो उर्वरक, बायो डी कंपोजर, वॉटर सॉल्यूबल और साथ में तरल कंसोटिया के बारे में जानकारी दी गई। इफको के द्वारा दिए जाने वाले संकट हरण बीमा योजना के बारे में सभी को बताया गया। कार्यक्रम में नैनो उर्वरकों का पिछले कुछ वर्षों से लगातार उपयोग करने वाले किसान श्री भूषण साहू के द्वारा भी बताया गया कि, नैनो उर्वरकों का उपयोग कर के दानेदार खाद की मात्रा 50 प्रतिशत तक कम की जा सकती है, जो कि भूषण साहू जी खुद कर रहे हैं अपने खेत पर इसका उपयोग कर फायदे देख चुके हैं। इसके पश्चात झाल खम्हरिया समिति में नीम का पौधारोपण किया गया।

राजनांदगांव जिले में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण

राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में निर्धारित गतिविधि अनुसार पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने की दिशा में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण जिला संघ राजनांदगांव के कार्यक्षेत्र में कार्यरत कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर सहकारिता से जुड़े जनप्रतिनिधिगण, उप आयुक्त श्री एनएल टंडन, सहायक उप आयुक्त श्री आरके झा, जिला सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव के प्राधिकृत अधिकारी श्री आलोक सिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी छुरिया श्री शशिकांत श्रीवास सहित सहकारिता विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण,

सहकारी समितियों के कर्मचारीगण एवं कृषक सदस्यगण वृहत संख्या में वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। उपरोक्त जानकारी एक साहू प्रभारी प्रबंधक जिला सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव ने दी।

सहकारिता और पंचायत मिलकर कर सकते हैं महिलाओं का आर्थिक विकास : बोदरी बघेल

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी केंद्र सेमरा मे महिलाओं का सहकारी प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद द्वारा 17 जुलाई को आयोजन किया गया। सेमरा पंचायत के सरपंच श्रीमती बुदरी बघेल द्वारा कहां गया कि महिलाओं का आर्थिक विकास सहकारिता विभाग तथा पंचायत विभाग के सहयोग से ही संभव है महिलाएं सहकारिता से समृद्धि ला सकती है महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, लाभ, नई समिति के पंजीयन की विधि के बारे में बताया गया।

मारेंगा की महिलाओं ने लिया सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी केंद्र मारेंगा में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद झा ने 15 जुलाई को सहकारी प्रशिक्षण रखा। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, लाभ, उद्देश्य, सहकारिता से समृद्धि लाने के उपाय सहकारिता के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना, नए सहकारी समिति के पंजीयन की विधि बेरोजगारों को सहकारिता के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के विषय में जानकारी प्रदान किया गया। महिला बाल विकास के कर्मचारी दिनमणि के द्वारा महिलाओं और छोटे बच्चों को पौष्टिक भोजन के बारे में तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के विषय से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के सफ्ल आयोजन में संपर्क साधक सुदन मौर्य का विशेष योगदान था।

बोरपदर आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं को मिला सहकारिता का ज्ञान

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम बोरपादर के आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 15 जुलाई को किया गया। जिसमें सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, सदस्यता सदस्य के अधिकार, कर्तव्य, बैंक लिंकिंग, व्यवसाय विकास, मछली पालन आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया। जिसे सफ्ल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

डिमरापाल की महिलाओं ने लिया सहकारी प्रशिक्षण

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी केंद्र डिमरापाल में महिलाओं को सहकारी प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद झा द्वारा 18 जुलाई को दिया गया। प्रशिक्षण में सहकारिता से समृद्धि प्राप्त करने के विषय में तथा आधुनिक युग में सहकारिता से आत्म निर्भर बनने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मत्स्य सहकारी समिति तथा दुग्ध सहकारी समिति के विषय में भी प्रकाश डाला गया। नए सहकारी समिति के पंजीयन की विधि के बारे में भी बताया गया है।

सुकमा जिले के लेदा में किसानों को मिला सहकारी प्रशिक्षण

सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के साथ-साथ सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशिक्षण इकाई के माध्यम से निरंतर सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में संघ के संभागीय कार्यालय जगदलपुर में कार्यरत मुख्य प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे सुकमा जिले के लैम्पस तोंगपाल के आश्रित ग्राम लेदा में 16 को प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कृषकों को सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पंचायत भवन में आयोजित सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान

कृषक बंधुओं के साथ-साथ युवाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत पर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सहकार से समृद्धि लाने हेतु जहां कृषि के लिए सहकारिता का विकास आवश्यक है, वहीं युवाओं को भी सक्षम बनने हेतु सहकारी समितियों का निर्माण आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान सहकारी समितियों का गठन पंजीयन की व्यवस्था के साथ-साथ सहकार की भावना की स्थापना हेतु एक सबके लिए और सब एक के लिए की भाव के साथ दुग्ध एवं मत्स्य सहकारिता की स्थापना कर आर्थिक समृद्धि लाने के बारे में ज्ञान करवाया गया। वर्ग को सफ्ल बनाने में ग्राम के सरपंच कुमारी दयावती एवं पंचायत प्रतिनिधियों केसाथ-साथ संघ के रोमांचल पाणिग्राही का सहयोग रहा।

एनसीडीसी उत्कृष्ट पैक्स समितियों को करेगी सम्मानित, 31 अगस्त तक मंगाए गए नामांकन

प्राथमिक स्तर की समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना और उनकी भूमिका को मान्यता देना है पुरष्कृत करने का उद्देश्य

रायपुर। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा **'एनसीडीसी सहकारी उत्कृष्टता व योग्यता क्षेत्रीय पुरस्कार 2025'** के लिए प्रदेश के प्राथमिक सहकारी समितियों से 31 अगस्त 2025 तक नामाकंन मंगाया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने देश के सहकारी विकास में सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई भूमिका भूमिका को पहचानने के लिए राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियों को हर दो साल में सहकारी उत्कृष्टता और योग्यता के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना शुरू की है।

योजना का उद्देश्य –

समितियों की भूमिका को मिलेगी मान्यता

i) देश के सहकारी विकास के लिए सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। ii) जमीनी स्तर की सहकारी समितियों यानी प्राथमिक स्तर की समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को मान्यता देना। iii) सहकारी समितियों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में एनसोडीसी की भूमिका का प्रचार-प्रसार करना है।

नई पहल करने वाली समितियां पुरष्कार का भागीदार बनेंगी

चूंकि 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए वर्ष 2025 में NCDC क्षेत्रीय पुरस्कार सहकारी क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों को अपनाने वाली सहकारी समितियों तथा अच्छे काम करने वाले सहकारी एफ्मीओ को भी मान्यता देंगे और पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति करेंगे।

चार सदस्यीय समिति करेगी विजेताओं का चयन

सहकारी समितियों का चयन सचिव (सहकारिता) या आयुक्त (सहकारिता) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर गठित चार सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाएगा और क्षेत्रीय निदेशक, NCDC, रायपुर इसके सदस्य संयोजक होंगे। इस संबंध में NCDC द्वारा विस्तृत योजना दिशानिर्देश, भाग लेने वाली समितियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप, समितियों के चयन में अपनाए जाने वाले मानदंड के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई हैं।

इन वर्गों में मिलेंगे पुरष्कार

एनसीडीसी क्षेत्रीय पुरस्कार सहकारी एफ्मीओ सहित दस (10) प्राथमिक सहकारी समितियों को दिया जाएगा। पुरस्कार में पाँच (5) प्रथम पुरस्कार सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं जिसमें 35,000 रुपये का नकद पुरस्कार और मान्यता/प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और पाँच (5) द्वितीय पुरस्कार सहकारी योग्यता पुरस्कार - जिसमें 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और मान्यता/ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रीय पुरस्कार योजना, दिशानिर्देश (अनुबंध-I), पात्र समितियों द्वारा भरा जाने वाला आवेदन पत्र (अनुबंध-II), चयन मानदंड (अनुबंध-III) और श्रेणी 3 के तहत समिति का चयन करने के लिए चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए एमओसी पहलों की सूची (अनुबंध-IV) तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं को मिली रोजगार, आवास पूर्णता में निभा रहीं हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

रायपुर। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका स्वयं का पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना आज जरूरतमंद लोगों के इस सपने को साकार कर रही है। योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों के सपनों का आशियाना बनकर तैयार है, जिसमें वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहें हैं। योजना से कई परिवार समाज में सम्मानजनक और स्थिर जीवन व्यतीत कर रहें हैं। सरगुजा जिले की महिलाएं ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, सेटरिंग प्लेट जैसी गतिविधियों के माध्यम से नियमित आय प्राप्त कर रही है, जिससे जिले कि कुल 465 महिलाएं लखपति दीदी क्लब में शामिल हो गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक ओर जहां लोगों को आवास प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सरगुजा जिले की महिलाओं ने इस योजना को आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बना लिया है। स्व-सहायता समूह की महिलाएं आवास निर्माण

हेतु निर्माण सामग्री प्रदान कर आवास पूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहीं हैं। समूह की दीदियों द्वारा समूह से लोन प्राप्त कर योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, सेंटरिंग सामान एवं मिक्सर मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरगुजा जिले के समूह की 281 दीदियों के द्वारा ईंट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं 413 दीदियों के द्वारा बैंक लिंकेज और समूहों से लोन लेकर सेंट्रिंग प्लेट्स को किराए में देने का व्यवसाय किया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 दीदियों के द्वारा लोन राशि और अपने परिवार की सहायता से सीमेंट मिक्सर मशीन को खरीद कर किराए में लगाया गया है। वहीं 06 दीदियों के द्वारा सीमेंट गिट्टी व छड़ आदि सामग्रियों को ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

सेंटरिंग प्लेट आपूर्ति ने महिला समूहों को दिखाई नयी राह

रायपुर। सेंटरिंग प्लेट का निर्माण परम्परागत रूप से पुरूष प्रधान रहा है, लेकिन अब रायगढ़ जिले की 100 स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने लोन लेकर सेंटरिंग प्लेट निर्माण का कार्य शुरू किया है। ये कार्य महिलाओं को न केवल एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान कर रहे है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में इनसे निमार्ण एवं विकास कार्य को गति मिली है, और महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हुई हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामूहिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। रायगढ़ विकास खण्ड में लगभग 100 समूह की महिलाओं ने संकुल एवं ग्राम संगठन से सीआईएफराशि के तहत 60 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त किया है।

लोन की इस राशि से महिलाओं ने सेंटरिंग प्लेट बनवा कर उसे पीएम आवास सहित गांवों में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिए किराये पर उपलब्ध करवा रही हैं।

इससे वे अब उद्यमिता की नई राह पर भी बढ़ चली हैं।

पीएम आवास से निकला आजीविका का मौका

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में इन सेंटरिंग प्लेट की आपूर्ति होने से निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, पीएम आवास निर्माण में भी तेजी आई है।

जैविक कृषि की नई पहचान श्री विधि और कतार रोपा से खेतों में क्रांति

दंतेवाड़ा। जिला प्रशासन, कृषि विभाग और भूमगादी की संयुक्त पहल से दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पारंपरिक खेती के विकल्प के रूप में अब श्री विधि, कतार रोपा और जैविक तरीकों को अपनाकर किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जिले को जैविक जिला बनाना है, जहां पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

इस अभियान के तहत पहली बार जिले में 6 हजार हेक्टेयर भूमि पर रोपा, कतार रोपा एवं श्री विधि से खेती का लक्ष्य तय किया गया है। यह पद्धतियां न केवल अधिक उत्पादन दे रही हैं, बल्कि जल संरक्षण, कीट नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी मददगार साबित हो रही हैं। आज 19 जुलाई 2025 को गीदम विकासखंड के ग्राम हीरानार में इस अभियान की जमीन पर प्रभावी शुरुआत हुई। उपसंचालक कृषि सूरज पंसारी, सहायक संचालक कृषि धीरज बघेल, भोले लाल पैकरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किशन नेताम समेत विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने कृषक लूदरु राम व अन्य किसानों के खेतों में कतार रोपा पद्धति का

प्रायोगिक प्रदर्शन किया। इन प्रयासों के जरिए किसानों को खेत में ही प्रशिक्षण देकर वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खेती की सफलता की बुनियाद किसानों को सशक्त बनाना है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर जैविक खाद निर्माण, बीज उपचार, जैविक कीटनाशक जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, घनजीवामृत आदि के उपयोग की जानकारी व्यावहारिक तौर पर दे रहे हैं। 'देखो और सीखो' की इस पद्धति से किसानों में व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

श्री विधि से खेती में जल की बचत, पौधों का बेहतर विकास और उत्पादन में 30-40 प्रतिशत तक वृद्धि देखी जा रही है। वहीं कतार रोपा से पौधों में उचित दूरी रखने के कारण कीट और रोग नियंत्रण आसान हो जाता है। जैविक विधियों के माध्यम से खेती की लागत घट रही है और उपज की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से मौजूद संसाधनों जैसे गौवंश, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और गौठानों कृ का प्रभावी उपयोग करते हुए प्राकृतिक कृषि मॉडल को अपनाया जा रहा है। इससे खेती में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और किसान रासायनिक इनपुट्स पर निर्भर नहीं रह रहे।

इस अभियान में जिले के प्रगतिशील किसान भी आगे आकर भूमिका निभा रहे हैं। वे स्वयं जैविक खेती अपना कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। 'किसान से किसान तक' ज्ञान के इस आदान-प्रदान ने अभियान को जन-आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। यह पहल सिर्फ उत्पादन और आय में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों की दिशा में भी सकारात्मक असर डाल रही है। आने वाले समय में इस मॉडल को जिले की प्रत्येक पंचायत में विस्तारित कर दंतेवाड़ा को एक राष्ट्रीय जैविक मॉडल जिले के रूप में स्थापित करने की योजना है। जिला प्रशासन, कृषि विभाग और भूमगादी की यह साझी कोशिश न केवल खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बना रही है, बल्कि जैविक क्रांति के पथ पर अग्रणी भी बना रही है।

करंजी लैम्पस में बस्तर कलेक्टर ने लगाया पौधा

लैम्पस समिति सदस्यों के साथ पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीण भी रहे मौजूद

जगदलपुर। 'एक पेड़ मां के नाम' की संकल्पना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की थीम सहकार से समृद्धि के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित करंजी ने शनिवार को धान उपार्जन केन्द्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन 19 जुलाई को रखा। इस कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्टर बस्तर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर श्री हरिस एस द्वारा पौधरोपण कर अन्य लोगों को भी पौधरोपण करने सहित पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनने का संदेश दिया गया।

इस दौरान लैम्पस समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों, क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारियों तथा किसानों एवं ग्रामीणों और अधिकारी- कर्मचारियों ने भी पौधरोपण में उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस मौके पर उपायुक्त सहकारी संस्थाएं सुश्री ऊषा ध्रुव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर श्री केएस ध्रुव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एसए रजा, बैंक के आंतरिक अंकेक्षक एवं विपणन अधिकारी श्री एसके कनौजिया सहित अन्य अधिकारी और पंचायत पदाधिकारी तथा आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के सदस्य, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी तथा क्षेत्र के कृषक एवं ग्रामीणजन भी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर के द्वारा उक्त आयोजन पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक सहभागिता तथा सहकारिता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया।

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम छेटे तामाकोन पारा के आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 12 जुलाई को किया गया। जिसमें सहकारिता का अर्थ महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, सदस्यता सदस्य के अधिकार, कर्तव्य बैठकें, व्यवसाय विकास, बैंक लिंकिंग आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया।

संगम अभियान महिलाओं को कर रही है आर्थिक रूप से मजबूत

रायपुर। जिला प्रशासन कोरिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में संगम अभियान के तहत निरंतर प्रभावशाली प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में विकासखंड सोनहत की ग्राम पंचायत तंजरा में मनरेगा श्रमिक परिवारों की महिलाओं को पशुपालन पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 35 महिला हितग्राहियों ने सक्रिय भागीदारी की।

यह प्रशिक्षण विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बकरी शेड, मुर्गी शेड, सुकर पालन शेड जैसी पशुपालन इकाइयाँ प्रदान की गई हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनके पशुधन संसाधनों का वैज्ञानिक व व्यावसायिक उपयोग सिखाना था, ताकि वे इन गतिविधियों से स्थायी आय अर्जित कर सकें।

व्यवस्थित मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण : इस प्रशिक्षण में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामस्वरूप चंदे द्वारा बकरी पालन, मुर्गी पालन व सूकर पालन की आधुनिक वैज्ञानिक विधियाँ, रोग प्रबंधन, पोषण, टीकाकरण, एवं साफ-सफाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महिलाओं ने पशुपालन से जुड़ी अपनी जिज्ञासाएं खुलकर रखीं, जिनका समाधान विशेषज्ञ द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी और बिहान टीम के सदस्य उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों में उत्साह और सीखने की ललक स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

50 परिवारों को मिला पशुपालन शेड का लाभ: ग्राम पंचायत तंजरा में अब तक 50 मनरेगा श्रमिक परिवारों को पशुपालन से संबंधित शेड स्वीकृत कराए जा चुके हैं। इन्हें बिहान समूहों से जोड़ते हुए लखपति दीदी अभियान के तहत आयवर्धक गतिविधियों से सशक्त किया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की दिशा में एक व्यवस्थित और प्रभावशाली प्रयास है।

चिरायु योजना : 8 वर्षीय बालिका निधि की आंखों को मिली नई रोशनी

सिम्स में किया गया मोतियाबिंद का नि:शुल्क सफल ऑपरेशन

रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के अंतर्गत बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में मुंगेली जिले की 08 वर्षीय बालिका निधि सारथी के ऑख में मोतियाबिंद का सफल आपरेशन किया गया। इससे निधि के आखों को नई रोशनी मिल गई। अब बच्ची को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। मुंगेली कलेक्टर ने बच्ची के बेहतर ईलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में विभाग द्वारा बच्ची को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

डॉ. शीला साहा ने बताया कि निधि के आंख में जन्म से ही मोतियाबिंद की समस्या थी, जिसके कारण उसे देखने में काफी समस्या होती थी, इससे उसकी पढ़ाई-लिखाई में परेशानी होती थी। चिकित्सकों ने इस समस्या से निजात दिलाने आपरेशन कराने की सलाह दी। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने निधि के आंख का आपरेशन कर कृत्रिम लेंस लगाया है, जिससे निधि को साफ-साफ दिखाई देने लगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री गिरीश कुर्रे ने बताया कि चिरायु योजनांतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को जन्मजात विकृति जैसे कटे-फटे होंठ, मोतियाबिंद, टेढ़े-मेढ़े अंग, श्रवण बाधा आदि के उपचार की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। जरूरत पड़ने पर उच्चस्तरीय संस्थानों में रेफर उपचार भी कराया जाता है। चिरायु योजना के तहत निधि को लाभान्वित किया गया, जिससे अब उसे साफदिखाई देने लगी और वह अपनी शिक्षा जारी रख सकी है।

ग्राम डोंगरीगुड़ा में सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन

बस्तर। प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही ने 17 व 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला बस्तर के ग्राम डोंगरीगुड़ा में सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत भवन में सदस्य वर्ग का आयोजन किया गया जिसमें कृषक भाइयों की उपस्थिति रही। प्रशिक्षण में सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, और विकास सहकारी ढांचा, सदस्यता सदस्य के अधिकार कर्तव्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, आमसभा, ऋणनीति, व्यवसाय विकास आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 : 'सहकार से समृद्धि' के एक नए युग की ओर

राष्ट्रीय सहकार नीति (एनसीपी) 2025 का 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में शुभारंभ भारत के सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस नीति का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशभर के सहकारी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और विकास विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति में किया।

यह नीति ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनाने की दिशा में सहकारी आंदोलन एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में तैयार की गई है और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है।

भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं जिनमें 30 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। ये समितियाँ कृषि, डेयरी, मत्स्य, ऋण, आवास, विपणन, वस्त्र आदि जैसे विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सहकारिताएं ऐतिहासिक रूप से जन-केंद्रित संस्थाएं रही हैं, जो लोकतांत्रिक शासन, पारस्परिक लाभ और समान विकास की भावना पर आधारित हैं। इनकी भूमिका को मान्यता देते हुए, वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई ताकि इस क्षेत्र को संगठित, समर्थ और सशक्त बनाया जा सके।

एनसीपी 2025 का प्रारूप 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किया गया जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की। यह नीति 17 बैठकों और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं (अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना) में मिले सुझावों और विचार-विमर्शों के आधार पर समृद्ध की गई।

दृष्टिकोण (Vision): 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा के अनुरूप, सतत सहकारी विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देना।

लक्ष्य (Mission): एक मजबूत कानूनी, वित्तीय और संस्थागत ढांचा विकसित करना जो सहकारी समितियों को पेशेवर, सदस्य-प्रधान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम उद्यमों में परिवर्तित करे, जिससे वे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान कर सकें।

छह रणनीतिक मिशन स्तंभ

नींव को सुदृढ़ बनाना: कानूनी सुधार, डिजिटल शासन और सुलभ वित्तीय सेवाएं। उत्साहवर्धन को प्रोत्साहित करना: आत्मनिर्भर और गतिशील सहकारी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। सहकारिताओं को भविष्य के लिए तैयार बनाना: प्रौद्योगिकी का समावेश और व्यावसायिकता को बढ़ावा। समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच को गहराई तक ले जाना: महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को लक्षित करना। नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश: हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी में सहकारिताओं की भागीदारी। सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना: शिक्षा, कौशल विकास और नेतृत्व निर्माण। प्रत्येक स्तंभ को समयबद्ध रणनीतियों और मापनीय उद्देश्यों के साथ समर्थित किया गया है, जिनका क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाएगा।

कानूनी, वित्तीय और संरचनात्मक सुधार

स्तंभ I – नींव को सुदृढ़ बनाना के अंतर्गत, एनसीपी 2025 में सहकारिताओं को सशक्त बनाने हेतु व्यापक कानूनी और नियामक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया है:

राज्यों में मॉडल सहकारी अधिनियमों और उपविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्वायत्तता, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक चुनावों और व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित की जा सके। राज्यों को रजिस्ट्रार कार्यालयों के डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से डेटा एकीकरण, और पेपरलेस प्रशासन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को बहुउद्देश्यीय बनाया जाएगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कॉर्पोरेट्स को दी जाने वाली कर छूट और प्रोत्साहनों को अब सहकारिताओं तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कर समानता (Tax Parity) सुनिश्चित हो। अस्वस्थ सहकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा।

वित्तीय दृष्टिकोण से, यह नीति सहकारी साख संरचना (PACS-DCCB-StCB) को संरक्षित और विस्तारित करने पर केंद्रित है, ताकि सहकारिताएं आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें — जो कि प्रौद्योगिकी-आधारित अंब्रेला संस्थाओं और कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित होंगी।

जीवंत सहकारी अर्थव्यवस्था और निर्यात की संभावनाएं

स्तंभ II – उत्साहवर्धन को प्रोत्साहित करना के अंतर्गत, एनसीपी 2025 का उद्देश्य एक समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो सहकारिताओं द्वारा संचालित हो।

प्रत्येक जिले में मॉडल सहकारी गाँव विकसित किए जाएंगे, जो नवाचार और समावेशिता को प्रदर्शित करेंगे। जीआई टैग प्राप्त और विशेष उत्पादों जैसे शहद, कॉफी, रेशम और मसालों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक क्लस्टर बनाए जाएंगे।

'भारत' ब्रांड के अंतर्गत ब्रांडिंग और वैश्विक व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से बाजार में दृश्यता बढ़ाई जाएगी। सहकारिताओं को "एक जिला एक उत्पाद" (ODOP) और "निर्यात हब के रूप में जिले" (DEH) जैसी पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मोटे अनाज, दालें, तिलहन और एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने से खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सहकारी क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करने और इसकी पहुँच को 50 करोड़ नागरिकों तक बढ़ाने हेतु एक कार्यबल (Task Force) गठित किया जाएगा।

डिजिटल, शैक्षिक और अनुसंधान आधारित परिवर्तन

स्तंभ III – सहकारिताओं को भविष्य के लिए तैयार बनाना के तहत, नीति डिजिटल परिवर्तन पर विशेष बल देती है: कोऑपरेटिव स्टैक (Cooperative Stack) विकसित किया जाएगा, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लिए जा सकेंगे और इसे एग्री-स्टैक (Agri-stack) से जोड़ा जाएगा, ताकि वास्तविक समय में सब्सिडी और लाभ दिए जा सकें।

सहकारिताओं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म पर भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे बड़े बाजारों तक पहुँच सकें और ई-कॉमर्स के अवसर प्राप्त कर सकें।

एक राष्ट्रीय शीर्ष शिक्षा और प्रशिक्षण संगठन (Apex Education & Training Organization) स्थापित किया जाएगा, जो मौजूदा सहकारी संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करेगा और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करेगा।

सामाजिक उद्यम इनक्यूबेटर (SEIs) ग्रामीण उद्यमों में नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे।

संघ (Federations) प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) को परिभाषित करेंगे और क्षेत्रीय रेटिंग प्रणाली लागू करेंगे ताकि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सके।

सहकारी अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ, शोध सहायता, और स्थानीय भाषाओं में सीखने के केंद्र सहकारी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेंगे।

समावेशिता और नए क्षेत्रों में विस्तार

स्तंभ IV – समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच को गहराई तक ले जाना के अंतर्गत, यह नीति समानता और अवसर की पहुँच को प्राथमिकता देती है- महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों (SC/ST) तथा विकलांग व्यक्तियों की लक्षित रूप से भागीदारी को

प्रोत्साहित किया जाएगा। हथकरघा, वनोपज, मत्स्य पालन और आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के लिए विशेष समर्थन प्रदान किया जाएगा। लिंग-आधारित पृथक आंकड़ों (Gender-disaggregated data) का उपयोग नीति निर्धारण और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा। विद्यालय पाठ्यक्रमों में सहकारिता को शामिल किया जाएगा ताकि प्रारंभिक जागरूकता और प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिल सके।

स्तंभ V – नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश- विविधता को प्रोत्साहन

यह स्तंभ सहकारी समितियों के व्यवसायिक विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है:

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) और अन्य सहकारी समितियाँ अब बहुउद्देशीय व्यावसायिक केंद्रों में परिवर्तित की जाएंगी, जो निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगी:

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (सस्ती जेनेरिक दवा दुकानें) कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवाएं

एलपीजी (रसोई गैस) एवं ईंधन वितरण केंद्र ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति की मरम्मत और संचालन सेवाएं शहरी सहकारी संस्थाएं अब स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी-सक्षम सेवाएं और माइक्रो-इंश्योरेंस (सूक्ष्म बीमा) जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने चरण पादुका का किया वितरण

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में आज सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत गायत्री रोपणी नमदगिरी के समीप आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव एवं एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की चरण पादुका योजना का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चरण पादुकाएं प्रदान करते हुए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। चरण पादुका योजना के तहत सूरजपुर जिले में 61,413 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस अवसर पर आम का पौधा रोपित कर जिला स्तरीय वन महोत्सव एवं एक पेड़ मां के नाम 2.0 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत इस साल कैम्पा, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत 7 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ''किसान वृक्ष मित्र योजना'' के तहत् हितग्राहियों के निजी भूमि पर ढाई लाख क्लोनल नीलगिरी पौधों का रोपण भी किया जायेगा। सूरजपुर जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा योजना के तहत् तैयार किये गये पौधों का निःशुल्क वितरण भी ग्रामीणों को किया जा रहा है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि तेन्दूपत्ता संग्रहण के दौरान पैरों में कांटा, कंकड़ न चुभे। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, जिसे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने फिर से शुरू किया है। यह योजना तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। उन्होंने शत-प्रतिशत संग्राहक महिलाओं को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने की बात कही।

राष्ट्रीय सहकार नीति 2025: 'सहकार से समृद्धि' के एक नए युग की ओर.....

पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहकारिताएं निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान देंगी:

बायोगैस उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, एग्रोफॉरेस्ट्री (कृषि वानिकी) तथा सर्कुलर इकॉनमी (पुनरावृत्तीय अर्थव्यवस्था) की प्रथाओं को अपनाना, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (इंटरनेट) और ब्लॉकचेन आधारित लॉजिस्टिक्स।

युवा सहभागिता, कार्यान्वयन और निगरानी

स्तंभ VI – सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना युवाओं को इस आंदोलन के केंद्र में स्थापित करता है- देशव्यापी युवा जागरूकता अभियान स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जाएंगे। सहकारी क्षेत्र में करियर के लिए पेशेवर डिप्लोमा और प्रमाणन पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। सहकारी रोजगार एक्सचेंज पोर्टल की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं और सहकारी नौकरियों के बीच सेतु का कार्य करेगा। सहकारी शिक्षा और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों और फैकल्टी का एक समूह तैयार किया जाएगा।

क्रियान्वयन ढांचा (Implementation Framework)

इस नीति का क्रियान्वयन सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांत के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित की भागीदारी होगी-

राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee), जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री द्वारा की जाएगी। नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति (Policy Implementation and Monitoring Committee), जिसकी अध्यक्षता सहकारिता सचिव द्वारा की जाएगी।

मंत्रालय में एक समर्पित क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (Implementation Cell) और एक परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit – PMU) गठित की जाएगी।

क्षेत्रीय भागीदार:

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) तथा राज्य सहकारी विभाग।

एक समग्र कार्य योजना (Comprehensive Action Plan) समयसीमा सहित तैयार की जाएगी, जिससे क्रियान्वयन संगठित, पारदर्शी, और सुधारोन्मुख (course-corrective) हो सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 केवल एक नीति दस्तावेज़ नहीं है — यह जन-शक्ति आधारित विकास मॉडल के लिए एक दिशा-निर्देश (ब्लूप्रिंट) है। यह नीति परंपरा, नवाचार, समावेशिता और उद्यमशीलता को सहकारिता की व्यापक छाया में समेटती है। सभी हितधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, सहकारी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन के रूप में उभर कर सामने आएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि "विकसित भारत 2047" की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे।

जय हिंद! जय सहकार!

डॉ. किशोर कुमार बैनीवाल,
निदेशक
सहकारी प्रबंधन संस्थान, भोपाल
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद की इकाई

फूलों की खेती से एक साल में 10 लाख की कमाई

रायपुर। कभी धान की परंपरागत खेती करने वाले सरगुजा जिले के किसान दिनेश कुमार सिंह ने जब गुलाब की खेती शुरू की, तो शायद खुद भी नहीं जानते थे कि यह निर्णय उनकी किस्मत बदल देगा। आज वे दो एकड़ जमीन में पॉली हाउस के जरिए डच गुलाब की उन्नत खेती कर रहे हैं और प्रतिदिन 5,000 से अधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन कर लाखों रुपये कमा रहे हैं। उनकी इस सफलता ने जिले के अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया है कि कैसे पारंपरिक खेती से हटकर नवाचार और आधुनिक तकनीक अपनाकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।

दिनेश सिंह पहले की तरह धान की खेती कर रहे थे, जिसमें लागत तो अधिक थी लेकिन आमदनी बेहद कम। मौसम पर पूरी तरह निर्भर यह खेती हर साल नुकसान की आशंका लेकर आती थी। इस बीच जब उन्हें उद्यानिकी विभाग से गुलाब की खेती के बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने पॉली हाउस बनाकर फूलों की खेती का निश्चय किया। नाबार्ड से 63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और उद्यानिकी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उन्होंने लगभग 1.30 करोड़ रुपये की लागत से पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें से 93 लाख रुपये उन्होंने बैंक ऋण के रूप में लिए।

दिनेश के पॉली हाउस में डच रोज़ के साथ जुमेलिया और टॉप सीक्रेट प्रजाति के गुलाब उगाए जा रहे हैं। पॉली हाउस में वर्षभर खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम, तापमान नियंत्रित करने के लिए फेगर सिस्टम तथा पौधों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित माली द्वारा 'वाइंडिंग' की व्यवस्था की गई है। कमजोर कलियों को काटकर दो नई कलियों का विकास किया जाता है, जिससे फूलों की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों बेहतर होता है।

दिनेश बताते हैं कि गुलाब की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। सामान्य दिनों में एक गुलाब की कीमत 4 से 5 रुपये होती है, जबकि शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में यही कीमत 15 से 20 रुपये तक पहुंच जाती है। उनके गुलाब की मांग न केवल छत्तीसगढ़ में है, बल्कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी ऑर्डर मिलते हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें पॉली हाउस निर्माण, ड्रिप सिस्टम और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए शासन की ओर से सहायता मिली। साथ ही, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी दी, जिससे उनकी खेती व्यवस्थित और व्यावसायिक रूप ले सकी। गुलाब की खेती न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि इसमें मानसिक सुकून भी है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में जहां मौसम और बाजार की अनिश्चितता रहती थी, वहीं गुलाब की खेती में कम समय, कम पानी और सीमित संसाधनों में बेहतर आमदनी हो रही है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 671 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी, तेन्दूपत्ता बोनस वितरण, चरण पादुका वितरण योजना से लाखों संग्राहक परिवारों के जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि आयी है। तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य से अब संग्राहकों को अधिक आय होने लगी है। संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि अब तक 10.85 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 671 करोड़ रुपये से अधिक की पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जा चुका है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा किए जाने से वन क्षेत्र में रहने वाले गरीब और आदिवासी परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा है। इस राशि का भुगतान समितियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

श्री कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं के पैरों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए चरण पादुका वितरण योजना संचालित की जा रही है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता और जनकल्याण की मिसाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आदिवासियों और वनवासियों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। जिसके कारण लघु वनोपज संग्रहण के कार्य से जुड़े लाखों परिवारों को न केवल सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे अब अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक ज़रूरतें भी आसानी से पूरी कर पा रहे हैं।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों से सशक्तिकरण की राह पर मुंगेली

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा की अनुरूप मुंगेली जिला डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंगेली जिले के तीनों विकासखण्डों की 30 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना होने से ग्रामीणों को काफी सुविधा मिल रही हैं। पहले आय, जाति, निवास आदि कार्यों के लिए च्वाईस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ग्रामीणों को उनके घर के पास ही सभी सुविधाएं मिलने लगी है। इससे समय और धन दोनों की बचत हुई है।

भटगॉव के युवा लेखराम साहू ने बताया कि पहले पैसे जमा या निकासी के लिए 20 किलोमीटर दूर मुंगेली जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा केन्द्र खुलने से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। इससे ग्रामीणों को समय, मेहनत और यात्रा खर्च की बचत हो रही है। इसी तरह डिजिटल सेवा का लाभ लेने पहुंची गंगा साहू ने भी शासन की इस पहल की सराहना की। गंगा साहू ने कहा कि यह पहल ग्रामीण स्वावलंबन और पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में मददगार कदम है। इस पहल ने न सिर्फ आर्थिक रूप से गाँवों को मज़बूत किया, बल्कि युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर भी दिए।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू हुए थे एडीएसके

इस वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शासन द्वारा जिले के तीनों विकासखण्डों में पहले चरण मे 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया गया है। इन केन्द्रों में आमजनों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, रेलवे टिकट, छात्रवृत्ति, और जन्म-मृत्यु सहित जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज़ों सहित खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है। इससे गाँव के लोग पंचायत स्तर पर ही ज़रूरी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

मिलेट्स को बढ़ावा देने दंतेवाड़ा प्रशासन की अनूठी पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किसानों और ग्रामीण परिवारों के पोषण को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई है। जिला प्रशासन ने गीदम विकासखंड के 20 किसानों को पारंपरिक अनाजों कोदो, कोसरा और रागी की प्रोसेसिंग के लिए "मिलेट मिक्सी" मशीनें वितरित की हैं। इस पहल का उद्देश्य यह है कि किसान अब अपने ही घर में इन अनाजों की सफाई और पीसाई कर अपने खान-पान में भी शामिल कर सकें। किसान अपनी पैदावार (मिलेट्स) को बाजार में अच्छे दाम पर बेच सकें, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और गांवों में पोषण स्तर में भी सुधार होगा। इसके लिए जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने मिलेट्स उत्पादक किसानों को बधाई दी।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन के द्वारा योजनांतर्गत आने वाले समय में सभी मिलेट उत्पादक किसानों को प्रोसेसिंग उपकरण दिए जाएं। साथ ही गांवों में प्रशिक्षण और विपणन की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे किसान इन अनाजों से अधिक लाभ कमा सकेंगे।

यह पहल दंतेवाड़ा को एक 'मिलेट आधारित पोषण मॉडल जिला' बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। वितरण कार्यक्रम जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि विभाग की सभापति श्रीमती ममता मंडावी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में मिलेट्स से जुड़ी जानकारी और लाभ के बारे में चर्चा की गई। दंतेवाड़ा जिले में करीब 16 हजार हेक्टेयर भूमि में मिलेट्स फसलों की खेती होती है। कोदो, कोसरा और रागी जैसे अनाज फाइबर, आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन-बी से भरपूर और पोषण तथा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इनका सेवन मधुमेह, मोटापा और कब्ज जैसी समस्याओं में फायदेमंद है। रागी में तो सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। इन अनाजों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें कम पानी और खाद में भी उगाया जा सकता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को मिला सर्वश्रेष्ठ सहकारी बैंकिंग के लिए प्रथम पुरस्कार

जगदलपुर। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 44 वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर को सर्वश्रेष्ठ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकिंग के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक श्रीमती रीनी अजिथ और मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर कुंवर सिंह ध्रुव तथा मुख्य लेखापाल प्रदीप मजूमदार को प्रदाय किया गया। इस दौरान बैंक के सीईओ को शील्ड व प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इसी अनुक्रम में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तोकापाल के संबद्ध शाखा तोकापाल को सर्वश्रेष्ठ पैक्स सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न पहलों को अपनाने के लिए द्वितीय पुरस्कार कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग राम रणविजय सिंह द्वारा प्रबंधक लैम्पस तोकापाल बलराम सेठिया को प्रदाय किया गया।

ग्रामीणों को बेहतर सेवा देने पर मिला सम्मान

कलेक्टर बस्तर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर हरिस एस के निर्देश एवं कुशल मार्गदर्शन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या जगदलपुर द्वारा बस्तर अंचल में सहकार से समृद्धि ध्येय के अनुरूप उल्लेखनीय कार्य कर किसानों एवं ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर शनिवार को कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी हरिस द्वारा बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित समस्त अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देकर बस्तर की जनता को अनवरत सेवा प्रदान करने प्रोत्साहित किया गया।

लघु वनोपज के कर्मचारियों का लेखा प्रशिक्षण प्रारंभ

■ **राज्य सहकारी संघ में लघुवनोपज कर्मचारियों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण उदघाटित**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ के सहायक ग्रेड-3 स्तर के कर्मचारियों का 20 दिवसीय लेखा प्रशिक्षण का शुभारंभ 25 जुलाई को किया गया। रायपुर चौबे कॉलोनी स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षण केन्द्र में यह प्रशिक्षण 25 से 13 अगस्त तक आयोजित है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण में 11 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं।

प्रशिक्षण का शुभारंभ मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ के प्रशासकीय अधिकारी बृज गोपाल बंग एवं विशिष्ट अतिथि सीए कांती लाल जैन ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांती लाल जैन ने कहा कि, यह प्रशिक्षण सहायक ग्रेड-3 स्तर के कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाये जाने वाले विषयों की जानकारी श्री जैन ने दी। उन्होने सहकारिता मंत्रालय द्वारा बनाई गई सहाकरिता की नई नीति की भी जानकारी दी तथा प्रशिक्षण के दौरान इसमें प्रकाश डालने की जानकारी दी। उन्होने बताया कि पहले सहकारिता में काम बहुत था किन्तु लाभ नहीं था, इसी कमी को दूर करने के लिए सहकारिता मंत्रालय प्रयासरत है।

लेखा प्रशिक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि नकद लेनदेन के बजाय बैंक लेनदेन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि त्रुटियां ज्यादा होती है।

प्रशिक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हो सकते हैं : बृज गोपाल

मुख्य अतिथि प्रशासकीय अधिकारी बृज गोपाल बंग ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, इसका प्रशिक्षण का लाभ लेकर आप पदोन्नत हो सकते है, लेकिन इस प्रशिक्षण को सिर्फ पदोन्नत होने के लिए नहीं बल्कि नई तकनीक अपनाने तथा अपनी संस्था में प्रशिक्षण का उपयोग करके संस्था को लाभ पहुंचाने में भी करें। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण को ध्यान से सीखे, कोई भी कर्मचारी अपने वरिष्ठ कर्मचारी से सीखते है उसी का अनुसरण करते हुए कार्य करते है। इस अवसर पर राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकगण व कर्मचारीगण तथा प्रशिक्षणार्थीगण मौजूद थे।

रिटायर आईएएस बिपिन मांझी बने राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बिपिन मांझी को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में आदेश सहकारिता विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत जारी किया गया।

बिपिन मांझी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच के अधिकारी रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद अब उन्हें राज्य में सहकारी चुनावों की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले दो वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा की गई यह नियुक्ति सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बिपिन मांझी के अनुभव और प्रशासनिक दक्षता से उम्मीद की जा रही है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव और उनकी प्रक्रियाएं पहले से अधिक व्यवस्थित होंगी। यह निर्णय सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक छग राज्य सहकारी संघ रायपुर द्वारा मयंक ऑफसेट रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail: cgcoopnews@gmail.com